श्री रामदेव भंडारी: यह कोई कठिन मामला नहीं है..(व्यवधान)

श्री नरेश यादव: प्रधान मंत्री को सदन में आना चाहिए..(व्यवधान)

श्री सभापति: श्री दारा सिंह चौहान क्लैरीफिकेशन के लिए।

RE: MISREPORTING OF SPECIAL MENTION BY DOORDARSHAN

श्री दारा सिंह चौहान (उत्तर प्रदेश): सभापति महोदय, हमने कल स्पेशल मेंशन में आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में यह लाया था कि इस देश में रहने वाले राजभर और भर जिनकी संख्या कई करोड़ है, आजादी के 50 साल बाद भी इनकी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हमने आपके माध्यम से सरकार से मांग की थी कि जिस तरीके से शिड्यूल्ड कास्ट से भी इनकी बदतर स्थिति है, इस मुल्क में इस नाते से राजभर और भर बिरादरी को, जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जाए। लेकिन कल जब टी०वी० का प्रसारण हो रहा था तो इस बात को तोड़-मरोड़कर, संसद के समाचार को तोड़-मरोड़कर इसका उल्टा कहा गया कि हमने मांग की थी हाउस में कि राजभर और भर जाति को अनुसूचित जाति में शामिल न किया जाए। इस नाते से सभापति महोदय मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संसद पर इस देश में रहने वाली जनता का इतना विश्वास है—जिसका सीधा प्रसारण किया जाता है अगर इस संसद की कार्यवाही को इस तरीके से, गलत तरीके से प्रसारित किया जाएगा तो संसद पर से ही देश की जनता का विश्वास उठने लगेगा। इस नाते से मैं आपसे मांग करना चाहता हूं कि जो मैंने कल कहा था कि राजभर और भर बिरादरी को सरकार अनुसूचित जाति में शामिल करे, इस बात को हूबहू इनको पुनः प्रसारित करना चाहिए। और अगर जान-बूझ करके ऐसी गलती हुई है तो निश्चित रूप से खेद प्रकट करना चाहिए अपने प्रसारण में जिससे लोगों का विश्वास इस हाउस में रहे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SPECIAL MENTIONS (CONTD.)

Need for Government's negotiation with College and University Teachers on their 35-Point Demand

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय (पश्चिमी बंगाल): माननीय सभापति महोदय, सब से पहले मैं आपके माध्यम से सिकन्दर बख्त जी का ध्यान अपनी ओर चाहूंगी। उन्होंने इस हाउस की आबोहवा के बारे में कहा, कल हम लोगों ने पर्यावरण पर चर्चा की और यह भी देखा कि देश का इकोलोजीकल बैलेंस इतना बिगड़ गया है कि आबोहवा यहां भी कभी-कभी ऐसी शोरगुल वाली हो जाती है। इस सदन की आबोहवा के अनुकूल मैं बड़े ही शांतिप्रिय ढंग से एक मुद्दा उठाने जा रही हूं। सभापति महोदय, यह मुद्दा मैंने कल मांगा था, आज मुझे मिला, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देती हूं। विगत कल 21.7.98 को देश के विविध भागों से बड़ी संख्या में कालेज और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों ने राजधानी में पैदल मार्च के रूप में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। मैं आपके माध्यम से उनकी मांगों की ओर माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगी।

सभापति महोदय, किसी भी देश में शिक्षा के उन्नय का प्रश्न चार इकाइयों पर आधारित है। ये है शिक्षक शिक्षणसंस्थान, शिक्षार्थी एवं उपयुक्त पाठ्यक्रम। शिक्षकों की भूमिका इनमें सब से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि वही अन्य तीनों इकाइयों के बीच संयोजक सूत्र का काम करता है। दुनिया के जिन देशों ने शिक्षा जगत में उच्चतम मानदंड स्थापित किया है उन्हीं शिक्षकों को पर्याप्त सम्मान मिला है और उन्हें छोटी-छोटी मांगों को लेकर सड़कों पर नहीं उतरना पड़ा है। कल हमारे शिक्षकों ने अपनी जो 35 सूत्रीय मांगें ज्ञापन के रूप में मंत्री महोदय के पास भेजी हैं, मैं सदन का अधिक समय लेकर प्रत्येक मांग की चर्चा नहीं करना चाहती, पर उनकी मांगों में जो विशेष उल्लेख जैसे यू०जी०सी० द्वारा रस्तोगी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तावित वेतनमानों को मानना, रीडर से प्रोफैसर पद में पदोन्नति, राज्य सरकारों को पर्याप्त धनराशि मुहैया कराना, सभी श्रेणी के शिक्षकों तथा अन्य अकैडमिक एडमिनिस्ट्रेटरों, लायब्रेरियन, रजिस्ट्रार, कंट्रोलर आदि के लिए भी संशोधित वेतनमान से लाभान्वित करने का प्रावधान, पार्ट टाइम शिक्षकों को भी न्यायोजित अधिकार और समस्त रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति आदि शामिल है।